

भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य

प्रलिस के लयः

केंद्रीय बजट 2023-24, राजकोषीय घाटा, सब्सडि, पूंजीगत व्यय, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), भुगतान संतुलन, भारत का वदिशी ःण ।

मेन्स के लयः

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू, राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू ।

चर्चा में क्यों?

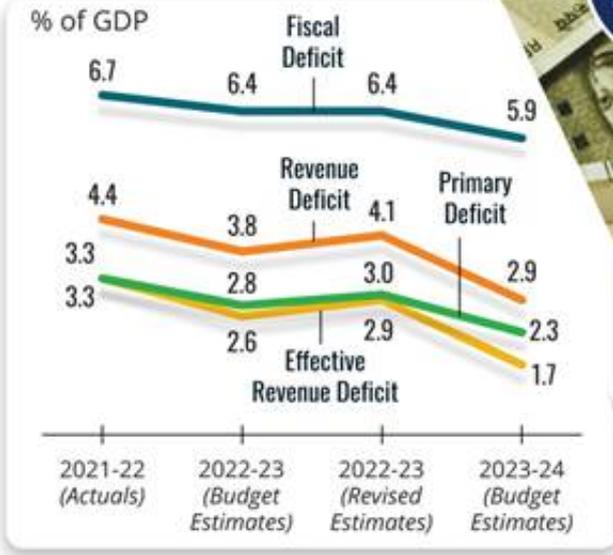
[केंद्रीय बजट 2023-24](#) में सरकार ने सापेक्ष राजकोषीय वविक को अपनाने की घोषणा की और ववित्त वर्ष 2024 में [राजकोषीय घाटे](#) में [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के 5.9% तक की गरिावट का अनुमान लगाया, जो ववित्त वर्ष 2023 में 6.4% था ।

- सरकार ने राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ का अनुसरण जारी रखने और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की योजना बनाई है ।

बजट में घाटे की प्रवृत्तियाँ:

- राजस्व घाटा ववित्त वर्ष 2022-23 के 4.1 प्रतशित (संशोधति अनुमान) की तुलना में ववित्त वर्ष 2023-24 में 2.9 प्रतशित रहने की उम्मीद है ।
- यद ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है जैसे प्राथमकि घाटा कहा जाता है, तो यह वर्ष 2022-23 (संशोधति अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 3% था ।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमकि घाटा, जो पछिले ब्याज भुगतान देनदारयिों से रहति चालू राजकोषीय रुख को दर्शाता है, GDP का 2.3% अनुमानति है ।

Trends in Deficit



राजकोषीय समेकन की दशा में सरकार के प्रमुख कदम:

■ कम सब्सिडी:

- सरकार ने भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम **सब्सिडी** हेतु आवंटित राशिको कम कर दिया है।
- वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- इसी प्रकार वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी 2,25,220 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,75,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम सब्सिडी 9,171 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में घटाकर 2,257 करोड़ रुपए किया गया है।
- वगित वर्ष की तुलना में सब्सिडी में कमी उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन यह अब भी वर्ष 2025-26 तक 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुँचने की दशा में एक सकारात्मक कदम है।

■ पूंजीगत व्यय:

- वर्ष 2023-24 के बजट में **पूंजीगत व्यय** को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है और सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को 50 वर्षों के लिये 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है।

■ ऋण प्रबंधन:

- अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और एक छोटा हिस्सा बचत, भविष्य नधि तथा बाहरी ऋण के बदले प्रतभूतियों से आता है।
- वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है, यह अनुमानतः 22,118 करोड़ रुपए है।
- **राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिये स्वतंत्र हैं, जिसमें 0.5% बजिली क्षेत्र के सुधारों के लिये है।**

उभरती अर्थव्यवस्था के लिये राजकोषीय समेकन का महत्त्व:

- राजकोषीय समेकन से तात्पर्य राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों से है। एक सरकार आमतौर पर घाटे को कम करने के लिये **करज़ लेती है**। इसके बाद उसे करज़ चुकाने के लिये अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना होता है।
- करज़ बढ़ने के साथ ब्याज का बोझ बढ़ता है। वित्त वर्ष 2022 के बजट में 34.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल सरकारी व्यय में से 8.09 लाख करोड़ रुपए (लगभग 20%) से अधिक ब्याज के भुगतान में खर्च हो गया।

राजकोषीय घाटा:

■ परिचय:

- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
 - यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिये कसि सीमा तक उधार लेना चाहिये और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- ऋण स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीतिकर्ज के बोझ में वृद्धि का कारण बन सकता है।
 - जबकि कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत हैं।
- राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू:
 - सरकारी खर्च में वृद्धि: राजकोषीय घाटा सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास के लिये काफी सहायक हो सकते हैं।
 - सार्वजनिक वित्त नविश: सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं जैसे दीर्घकालिक नविशों को वित्तपोषित कर सकती है।
 - रोजगार सृजन: सरकारी व्यय में वृद्धि से रोजगार सृजन हो सकता है, जो बेरोजगारी को कम करने और जीवन स्तर को ऊँचा करने में मदद कर सकता है।
- राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू:
 - बड़े हुए कर्ज का बोझ: लगातार उच्च राजकोषीय घाटा सरकारी ऋण में वृद्धि को दर्शाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज चुकाने का दबाव डालता है।
 - मुद्रास्फीति का दबाव: बड़े राजकोषीय घाटे से धन की आपूर्ति में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है।
 - नज्जी नविश में कमी: सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये भारी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और नज्जी क्षेत्र के लिये ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इस प्रकार नज्जी नविश बाहर हो सकता है।
 - भुगतान संतुलन की समस्या: यदि कोई देश बड़े राजकोषीय घाटे की स्थिति से गुजर रहा है, तो उसे विदेशी स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है और भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ सकता है।

भारत में अन्य प्रकार के घाटे:

- राजस्व घाटा: यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।
 - राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ
- प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान होता है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के मध्य अंतर को इंगित करता है तथा पछिले वर्षों के दौरान लिये गए ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु किये गए व्यय को ध्यान में नहीं रखता है।
 - प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
- प्रभावी राजस्व घाटा: यह पूंजीगत परसिंपत्तियों के निर्माण के लिये राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर है।
 - सार्वजनिक व्यय संबंधी रंगराजन समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

नषिकर्ष:

पूँजीगत व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उबारना भारत की प्राथमिकता है। बुनियादी ढाँचे में सरकारी नविश में वृद्धि के साथ नज्जी नविश भी बढ़ेगा, आर्थिक (GDP) विकास को बढ़ावा मलिया, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे के GDP अनुपात में कमी आएगी।

UPSC सविलि सेवा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. शासन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

- प्रत्यक्ष विदेशी नविश अंतरवाह को प्रोत्साहति करना
- उच्च शकिषण संस्थानों का नज्जीकरण
- नौकरशाही का आकार कम करना
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बकिरी/ऑफलोडगि

भारत में राजकोषीय घाटे को नयितरति करने के उपायों के रूप में उपर्युक्त में से कनिका उपयोग कयिा जा सकता है?

- केवल 1, 2 और 3
- केवल 2, 3 और 4
- केवल 1, 2 और 4
- केवल 3 और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिन्लखिति में से कौन-सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारक हो सकता है? (2021)

- (a) सार्वजनिक ऋण की चुकौती
- (b) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से उधार लेना
- (c) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये बैंकों से उधार लेना
- (d) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये नई मुद्रा का सृजन करना

उत्तर: (d)

प्रश्न: नमिन्लखिति में से कनिको/कसिको भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल कयिा जाता है? (2016)

1. सड़कों, भवनों, मशीनरी आदि जैसी परसिंपत्तियों के अधगिरहण पर व्यय
2. वदिशी सरकारों से प्राप्त ऋण
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण तथा अग्रमि

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना' है। इस उद्देश्य प्राप्त करने के लिये बजट 2017-18 सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का वशिलेषण कीजयिे। (मुख्य परीक्षा, 2017)

प्रश्न. पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजयिे। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-fiscal-deficit-targets>